

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

श्रीमती गीता देवी

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

2015 की विविध अपील सं.43

3 जनवरी, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या मूल दावेदार के प्रतिस्थापित कानूनी उत्तराधिकारी, जो मृतक पर निर्भरता साबित करने या अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहे, रेलवे दावा न्यायाधिकरण नियम के नियम 26 के तहत प्रतिस्थापन के आधार पर रेलवे अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा बनाए रख सकते हैं?

हेडनोट्स

रेलवे अधिनियम, 1989—धारा 123(बी), 124-ए, 125—रेलवे दावा न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989—नियम 26—मुआवजे के लिए दावा—आश्रित—कथित अप्रिय घटना में अविवाहित यात्री की मृत्यु—मूल दावेदार (मां) की विचाराधीनता के दौरान मृत्यु—नियम 26 के तहत प्रतिस्थापित कानूनी उत्तराधिकारी—मृतक पर निर्भरता का कोई सबूत नहीं—प्रतिस्थापित दावेदारों की पहचान स्थापित नहीं—मृतक के वास्तविक यात्री होने का कोई सबूत नहीं—जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया (एफआईआर, जांच, पोस्टमार्टम) उन्हें अप्रमाणित और अविश्वसनीय माना गया—न्यायाधिकरण ने दावा खारिज कर दिया—प्रतिस्थापित उत्तराधिकारियों द्वारा अपील दायर की गई। निर्णय: नियम 26 के अंतर्गत प्रतिस्थापन से मुआवजे का दावा करने का मूल अधिकार नहीं मिलता—केवल धारा 123(बी) के अंतर्गत "आश्रित" ही पात्र हैं—जहाँ मृतक यात्री अविवाहित है या नाबालिग है, वहाँ केवल उसके माता-पिता को ही आश्रित शब्द के अर्थ में रखा गया है—अपीलकर्ता निर्भरता या पहचान साबित करने में विफल रहे—टिकट या दुर्घटना स्थल का कोई साक्ष्य नहीं—दावा सही रूप से खारिज—न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश को बरकरार रखा गया—अपील खारिज।

(पैराग्राफ 3, 4, 15, 19, 28 से 38)

न्याय दृष्टान्त

तुरतन समद बनाम भारत संघ, 2021 दुर्घटना दावा जर्नल (एसीजे) 2042; अजय कुमार पंडित और अन्य बनाम भारत संघ, 2020 एससीसी ऑनलाइन झारखंड 1660: (2021) एसीजे 1628; कृष्णकुमार. जी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2011 एससीसी ऑनलाइन केरेला 4231: 2013 एसीजे 1068; अर्थमुडी रामू और अन्य बनाम भारत संघ, 2007 (1) परिवहन और दुर्घटना मामले 948 (ए.पी.); एम. वीरप्पा बनाम एवलिन सिकेरिया की रिपोर्ट ए आईआर 1988 एससी 506 में दी गई है; भारत संघ बनाम कुमारी दीप्ति (माइनर), एआईआर 2000 पंजाब और हरियाणा 105—विशिष्ट किया गया।

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून; भारत का संविधान, 1950; बिहार पदों और सेवा में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991; दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016।

मुख्य शब्दों की सूची

व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, दावा, आश्रित, जहां मृतक यात्री अविवाहित है या नाबालिग है, वहां केवल उसके माता-पिता को ही आश्रित शब्द के अर्थ में रखा गया है।

प्रकरण से उत्पन्न

तीजा देवी द्वारा रेलवे अधिनियम के तहत अपने बेटे संजय खटीक की मृत्यु के लिए दायर किए गए मुआवजे के दावे से, जिसकी कथित तौर पर 11.03.2002 को ट्रेन से यात्रा करते समय एक अप्रिय घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने दावा जारी रखने की मांग की।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री कृष्ण मोहन मुरारी, अधिवक्ता।

भारत संघ की ओर से: श्री अवधेश कुमार पांडे, वरिष्ठ सीजीसी; श्री लोकेश, वरिष्ठ सीजीसी के ए.सी।

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2015 की विविध अपील सं.43**

=====

श्रीमती गीता देवी, माता-स्वर्गीय तीजा देवी, पति-श्री तुलसी प्रसाद, निवासी-ग्राम तकिया बाजार, डाक तकिया बाजार, थाना सासाराम, जिला रोहतास बिहार

... .. अपीलार्थी

बनाम

1. महाप्रबंधक, पूर्वी रेलवे, 3-कोएलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के माध्यम से भारत संघ।
2. रामू उर्फ रामू खटिक, पिता-स्वर्गीय मोहन खटिक, निवासी-ग्राम तकिया बाजार, डाक तकिया बाजार, थाना सासाराम एम, जिला रोहतास, बिहार।

... .. उत्तरदाताओं

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी के लिए : श्री कृष्ण मोहन मुरारी, अधिवक्ता
भारत संघ के लिए : श्री अवधेश कुमार पांडे, वरिष्ठ सीजीसी,
श्री लोकेश, वरिष्ठ सीजीसी के एसी

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

दिनांक : 03-01-2023

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मोहन मुरारी और भारतीय संघ (पूर्वी रेलवे) के अधिवक्ता श्री लोकेश की सहायता से रेलवे के विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पांडे को सुना। उत्तरदाता सं. 2 का प्रतिनिधित्व एकमात्र अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया जाता है।

2. अपीलार्थी दावा रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना पीठ, पटना (इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) के विद्वान सदस्य (तकनीकी) द्वारा आवेदन सं. ओ.ए.000177/2002 में पारित किए गए दिनांक 24.04.2013 आक्षेपित आदेश से व्यथित

और असंतुष्ट है जिसके तहत विद्वान न्यायाधिकरण ने दावे के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि :- (i) आवेदक यह स्थापित करने में विफल रहे कि स्वर्गीय संजय या तो ट्रेन संख्या का एक वास्तविक यात्री था। 054 ईएमयू 11.03.2002 पर या उस दिन किसी भी अप्रिय घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि दावा किया गया है, (ii) श्रीमती गीता देवी और रामू की पहचान की स्थापना नहीं हुई थी। श्रीमती. गीता देवी ने 16.07.2012 पर दायर प्रतिस्थापन याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके अलावा गीता देवी के मतदाता पत्र से पता चल रहा था कि संजय की मृत्यु के समय उनकी आयु 22 वर्ष थी, (iii) मृतक की आयु भी संदिग्ध बनी हुई है; और (iv) तीजा देवी ने अपने दावे के आवेदन में कभी भी गीता देवी और रामू को सह-आवेदक नहीं बनाया। अपना दावा दायर करते समय उन्होंने कोई निर्भरता प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया था।

मामले के संक्षिप्त तथ्य

3. अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि तीजा देवी नामक एक व्यक्ति ने विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 09.07.2002 का मूल आवेदन दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि उनके पुत्र स्वर्गीय संजय खटिक (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) 11.03.2002 पर मुगलसराय से सासाराम जा रहे थे 054 ईएमयू पैसेंजर द्वारा यात्रा करते समय की एक अप्रिय घटना में मृत्यु हो गई थी। अपने आवेदन में उसने एक विशिष्ट बयान दिया कि वह मुआवजे के लिए एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी थी। मृतक अविवाहित था। इसलिए, उसने, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 125 (इसके बाद "1989 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत आवेदन दायर करते हुए मुआवजे के रूप में रु. 4,00,000/- (चार लाख) का दावा किया।

4. यह अभिलेख से आगे पता चलता है कि दिनांक 09.07.2002 का एक आदेश एक आवेदन दाखिल करने का उल्लेख करता है। इसे पंजीकृत करने के लिए आदेश लिखा जाता है और आवेदन की प्रति उत्तरदाताओं को दी जाती है और जवाब 05.09.2002

तक दाखिल किया जाये। हालाँकि, अतिरिक्त/सहायक पंजीयक के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके बाद, फिर से एक अजीब तरीके से एक आदेश है "26.03.2012 पर बेंच के सामने रखें।" 09.07.2002 और 26.03.2012 के बीच लगभग दस (10) वर्षों की अवधि के दौरान क्या हुआ, यह ज्ञात नहीं है। इसके बाद, 04.04.2012 पर मुद्दे तैयार किए गए। 15.05.2012 पर। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि तीजा देवी नहीं रहीं। 14.01.2011 पर उनकी मृत्यु हो गई।

एक वर्ष से अधिक समय के बाद स्वर्गीय तीजा देवी के नाम को हटाने और उनकी विवाहित बेटी श्रीमती गीता देवी और अविवाहित पुत्र रामू जिन्हें मूल आवेदक का कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि कहा जाता था को प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना के साथ देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ एक प्रतिस्थापन याचिका 02.07.2012 पर दायर की गई थी। प्रतिस्थापन आवेदन को दिनांक 16.07.2012 के आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया था और दोनों आवेदकों को आ.सा.1 और आ.सा.2 के रूप में गवाही देने का निर्देश दिया गया था। उन्हें प्रस्तावित गवाहों के शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

5. प्रतिस्थापन याचिका पर केवल रामू ने हस्ताक्षर किए थे। न्यायाधिकरण ने 13.08.2012 पर आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता को 03.09.2012 पर प्रतिपरीक्षण के लिए रामू को पेश करने का निर्देश दिया। रामू उस दिन उपस्थित होने में विफल रहे, और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा उनकी उपस्थिति के लिए निर्धारित तीन अन्य तिथियों के बावजूद रामू उपस्थित नहीं हुए।

6. जहाँ तक गीता देवी का संबंध है, यह पता चला है कि वह आवेदक गवाह सं. 1 के रूप में उपस्थित हुई, खुद को एक तुलसी प्रसाद नमक एक व्यक्ति की पत्नी के रूप

में बताया और बयान दिया कि एक 'पड़ोसी मामा' ने दुर्भाग्यपूर्ण दिन संजय के लिए रेल टिकट प्राप्त किया था और उसे मुगलसराय में ट्रेन संख्या 054 ईएमयू पैसेंजर में डाल दिया था। उसने दावा किया कि संजय ट्रेन से नीचे गिर गया लेकिन वह दुर्घटना स्थल का उल्लेख नहीं कर सकी। अपनी प्रतिपरीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि उसे घटना की तारीख नहीं पता थी और उसे इसकी कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी। विद्वान न्यायाधिकरण ने आक्षेपित आदेश में दर्ज किया है कि श्रीमती गीता देवी की पहचान भी निर्णायक रूप से साबित नहीं हुई। एओ/सासाराम द्वारा जारी मूल परिवार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और छायाप्रति में उनके पति का नाम नहीं था। यह आगे दर्ज किया गया कि गीता देवी की उम्र भी उनके वोटर आई कार्ड से अलग है।

7. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, विद्वान न्यायाधिकरण ने इस निर्णय के शीर्ष पर पहले से ही बताए गए कारणों के लिए दावे को खारिज कर दिया है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुति

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश पर इस आधार पर हमला किया है कि एकमात्र अपीलार्थी और उत्तरदाता सं. 2 स्वर्गीय तीजा देवी के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, इसलिए, उन्हें रेलवे दावा न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 (इसके बाद "1989 के नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 26 के संदर्भ में प्रतिस्थापित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के साथ-साथ उत्तरदाता सं. 2 को 1989 के अधिनियम की धारा 123 (बी) के तहत परिकल्पित "आश्रित" शब्द के अर्थ के भीतर शामिल किया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने 2021 दुर्घटना दावा पत्रिका (एसीजे) 2042 में प्रतिवेदित तुर्तन समद बनाम भारत संघ और 2020 एससीसी ऑनलाइन झार 1660 : (2021) एसीजे 1628 में प्रतिवेदित अजय कुमार पंडित और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे 2011 में एस.सी.सी. ऑनलाइन केर 4231 : 2013 ए.सी.जे. 1068 में

प्रतिवेदित कृष्णकुमार.जी. बनाम भारत संघ के मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और तर्क दिया की माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के साथ-साथ केरल उच्च न्यायालय के निर्णयों ने यह विचार रखा है कि मूल दावेदारों के कानूनी उत्तराधिकारी 1989 के नियमों के नियम 26 के संदर्भ में कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने मामले में 2007 (1) परिवहन और दुर्घटना मामले 948 (ए.पी.) में प्रतिवेदित अर्थमुदी रामू और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और यह तर्क दिया कि मृत्यु पर क्षति के लिए मुआवजे के मामले में मूल कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने का अधिकार मौजूद होगा।

रेलवे की ओर से प्रस्तुति

10. दूसरी ओर, रेलवे के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विद्वान न्यायाधिकरण के आदेश के केवल अवलोकन पर, यह प्रतीत होगा कि यह अपीलार्थी तथा उत्तरदाता सं.2. की ओर से किया गया दवा झूठा और फर्जी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश को पढ़ने पर यह प्रतीत होता है कि आर-2 ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें दिए गए कई अवसरों के बावजूद खुद को गवाही के लिए प्रस्तुत नहीं किया और जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, वह वह अपनी पहचान स्थापित नहीं कर सकी।

11. विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क करते हैं कि 1989 के अधिनियम की योजना को सरलता से पढ़ने पर, यह प्रतीत होता है कि धारा 124 या धारा 124-ए के तहत मुआवजे के लिए आवेदन केवल 1989 के अधिनियम की धारा 125 की उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) के तहत गिने गए व्यक्तियों द्वारा न्यायाधिकरण में दावा किया जा सकता है।

12. इस न्यायालय का ध्यान धारा 125 की उप-धारा (1) के खंड (सी) की ओर आकर्षित किया गया है जो विशेष रूप से नाबालिग के मामले से संबंधित है और इस प्रावधान के अनुसार जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, मुआवजे के लिए उसके अभिभावक द्वारा आवेदन दायर किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 125 के खंड (डी) के अनुसार जहां दुर्घटना या अप्रिय घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के किसी भी आश्रित द्वारा या जहां ऐसा आश्रित नाबालिग है, उसके अभिभावक द्वारा दायर किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि अपीलार्थी और उत्तरदाता सं. 2 के प्रतिस्थापन की मांग करने वाले आवेदन के सरल अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि वे कहीं भी मृतक पर निर्भर होने का दावा नहीं करते हैं। उन्होंने केवल इस आधार पर अपने प्रतिस्थापन का दावा किया कि वे स्वर्गीय तीजा देवी के कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि थे।

13. विद्वान अधिवक्ता, आगे विस्तार से तर्क करते हैं कि धारा 125 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक आश्रित द्वारा इन धाराओं के अंतर्गत मुआवजे के लिए किया गया आवेदन प्रत्येक अन्य आश्रित के लाभ के लिए होगा। इसलिए, उनके अनुसार, विधायिकाओं का इरादा केवल मृतक के 'आश्रित' या 'आश्रितों' को मुआवजा प्रदान करना है। यह उनका तर्क है कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी और उत्तरदाता सं 2 ने दावा किया कि वे स्वर्गीय तीजा देवी के कानूनी उत्तराधिकारी थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे मृतक पर निर्भर थे और उनके मृतक पर निर्भर होने के किसी भी सबूत के अभाव में, वे कोई मुआवजा नहीं मांग सकते हैं, भले ही वे स्वर्गीय तीजा देवी के कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करते हों। वे अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहे थे। यह तर्क दिया जाता है कि इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की गई थी और स्वर्गीय तीजा देवी को नहीं दी गई थी, जो मूल आवेदक थीं, इसलिए किसी भी मुआवजे की राशि के संबंध में कोई अधिकार उनके पास निहित नहीं था।

14. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय और माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों को उन मामलों के तथ्यों और उनमें शामिल मुद्दों के संदर्भ में अंतर किया गया है। यह न्यायालय इसके बाद उन निर्णयों पर विचार करेगा।

विचारणीय

15. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है। मामले के तथ्यों से पता चलता है कि स्वर्गीय तीजा देवी ने खुद को मृतक की मां होने का दावा किया था, उन्होंने 1989 के अधिनियम की धारा 123 के खंड (बी) के उपखंड (आई) के तहत "आश्रित" शब्द के अर्थ के तहत एक मूल आवेदन दायर किया था।

16. अपने आवेदन में, उसने जोर देकर कहा कि मृतक अविवाहित था और वह एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी थी। जिस तरीके से न्यायाधिकरण की आदेश-पत्रियाँ लिखी गई हैं, उसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। दावा याचिका कैसे दर्ज की गई और दस (10) वर्षों तक बिना किसी प्रगति के रही, यह ज्ञात नहीं है। मामला 26.03.2012 के बाद आगे बढ़ा, जबकि 14.01.2011 पर तीजा देवी की मृत्यु हो गई।

17. इस स्तर पर, 1989 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा ताकि अधिनियम की योजना और कानून के तहत ऐसे प्रावधान प्रदान करने के पीछे विधायिकाओं के इरादे की पूरी तरह से सराहना की जा सके। तैयार संदर्भ के लिए 1989 के अधिनियम के अध्याय XIII के तहत आने वाली 1989 के अधिनियम की धारा 125 की धारा 123 को तैयार संदर्भ के लिए यहाँ उद्धृत किया गया है:-

“अध्याय XIII

**दुर्घटनाओं के कारण यात्रियों की मृत्यु और चोट
के लिए रेलवे प्रशासन का दायित्व**

123. परिभाषाएँ।—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,—

(ए) "दुर्घटना" से धारा 124 में वर्णित प्रकृति की दुर्घटना है;
(बी) "आश्रित" से मृतक यात्री के निम्नलिखित रिश्तेदारों में से कोई भी हो सकता है, अर्थात्:—

(i) पत्नी, पति, पुत्र और पुत्री, और यदि मृतक यात्री अविवाहित है या नाबालिग है, तो उसके माता-पिता;

(ii) माता-पिता, नाबालिग भाई या अविवाहित बहन, विधवा बहन, विधवा बहू और पूर्व-मृत बेटे का एक नाबालिग बच्चा, यदि पूरी तरह से या आंशिक रूप से मृतक यात्री पर निर्भर है;

(iii) पूर्व-मृत बेटी का एक नाबालिग बच्चा, यदि वह पूरी तरह से मृत यात्री पर निर्भर है;

(iv) पैतृक दादा-दादी जो पूरी तरह से मृत यात्री पर निर्भर हैं;

[(सी) "अप्रिय घटना" का अर्थ है—

(1) (i) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा (3) की उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर आतंकवादी कार्य करना; या

(ii) हिंसक हमला करना या लूट-पाट या डकैती करना; या

(iii) दंगे, गोलीबारी या आगजनी में लिप्त होना,

यात्रियों को ले जाने वाली किसी ट्रेन में या उसमें सवार किसी व्यक्ति द्वारा, या प्रतीक्षा कक्ष, वस्त्र कक्ष या आरक्षण या टिकट घर में या किसी प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थान पर; या

(2) यात्रियों को ले जा रही ट्रेन से किसी भी यात्री का दुर्घटनावश गिरना।]

124. दायित्व का विस्तार।—जब एक रेलवे के काम करने के दौरान, एक दुर्घटना होती है, या तो ट्रेनों के बीच टक्कर होती है जिसमें से एक यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन है या, या यात्रियों को ले जा रही किसी रेलगाड़ी या उसके किसी भाग का पटरी से उतरना या अन्य दुर्घटना होना, फिर चाहे रेलवे प्रशासन की ओर

से कोई गलत कार्य, उपेक्षा या चूक हुई हो या नहीं, जैसे कि एक यात्री जो घायल हो गया है या जिसे कोई कार्रवाई करने और उसके संबंध में नुकसान की वसूली करने का अधिकार है, रेलवे प्रशासन, किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उस हद तक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो निर्धारित किया जा सकता है और उस हद तक केवल ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की मृत्यु के कारण हुए नुकसान के लिए और यात्री के स्वामित्व वाले माल की व्यक्तिगत चोट और नुकसान, विनाश, क्षति या गिरावट के लिए और उसके साथ उसके डिब्बे में या ट्रेन में, ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुआ हो।

स्पष्टीकरण।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "यात्री" में कर्तव्य पर तैनात एक रेलवे कर्मचारी शामिल है।

[124-A. अप्रिय घटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति।]— जब किसी रेलवे के काम करने के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है, तो रेलवे प्रशासन की ओर से कोई गलत कार्य, उपेक्षा या चूक हुई है या नहीं, जैसे कि एक यात्री जो घायल हो गया है या एक यात्री जिसकी मृत्यु हुई है उसका आश्रित, वह कार्रवाई बनाए रखने और उसके संबंध में नुकसान की वसूली करने का हकदार होगा, रेलवे प्रशासन, किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उस हद तक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो निर्धारित किया जा सकता है और उस हद तक केवल ऐसी अप्रिय घटना के परिणामस्वरूप एक यात्री की मृत्यु या चोट के कारण हुए नुकसान के लिए:

बशर्ते कि रेल प्रशासन द्वारा इस धारा के तहत कोई मुआवजा देय नहीं होगा यदि यात्री की मृत्यु हो जाती है या उसे निम्नलिखित कारणों से चोट लगती है -

- (ए) उसके द्वारा आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास;
- (बी) स्वयं को चोट पहुँचाना;
- (सी) उसका अपना आपराधिक कार्य;

(डी) नशे या पागलपन की स्थिति में उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य;

(ई) कोई प्राकृतिक कारण या बीमारी या चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपचार जब तक कि उक्त अप्रिय घटना के कारण हुई चोट के कारण ऐसा उपचार आवश्यक न हो जाए।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "यात्री" में शामिल हैं -

(i) कर्तव्य पर तैनात रेलवे कर्मचारी; और

(ii) एक व्यक्ति जिसने किसी भी तारीख या वैध प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से यात्रा करने के लिए एक वैध टिकट खरीदा है और एक अप्रिय घटना का शिकार हो जाता है।

125. मुआवजे के लिए आवेदन।—(1) एक आवेदन धारा 124 [या धारा 124-ए] के तहत मुआवजे के लिए दावा न्यायाधिकरण को किया जा सकता है -

(ए) उस व्यक्ति द्वारा जिसे चोट लगी है या कोई नुकसान हुआ है, या

(बी) इस संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी प्रतिनिधि द्वारा, या

(सी) जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, उसके अभिभावक द्वारा, या

(डी) जहां दुर्घटना, [या अप्रिय घटना] के कारण मृत्यु हुई है, मृतक के किसी आश्रित द्वारा या जहां ऐसा आश्रित नाबालिग है, उसके अभिभावक द्वारा।

(2) इस धारा के तहत मुआवजे के लिए आश्रित द्वारा प्रत्येक आवेदन प्रत्येक अन्य आश्रित के लाभ के लिए होगा।

18. चूँकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने 1989 के नियमों के नियम 26 पर भरोसा किया है, इसलिए यह न्यायालय उक्त नियम 26 को इसके नीचे उद्धृत करेगा :-

"26. कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन—(1) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी पक्ष की मृत्यु के मामले में,

मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि ऐसी मृत्यु की तिथि को अभिलेख पर लाए जाने के नब्बे दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

(2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, कानूनी प्रतिनिधियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, वहां कार्यवाही समाप्त हो जाएगी:

बशर्ते कि दिखाए गए अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए, न्यायाधिकरण मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की अनुमति दे सकता है।

19. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि 1989 के अधिनियम की योजना "आश्रित" को मुआवजा प्रदान करने के लिए है और "आश्रित" शब्द को धारा 123 के खंड (बी) के उपखंड (i) के तहत परिभाषित किया गया है एक मृत यात्री के मामले में जो अविवाहित है या नाबालिग है, उसके माता-पिता को ही परिभाषा के तहत शामिल किया जाएगा। विधायी आशय को समझने के लिए जब 1989 के अधिनियम की धारा 123 के खंड (बी) के उपखंड (ii) को शामिल किया जाता है, तो यह आसानी से पाया जा सकता है कि इस प्रावधान के अनुसार माता-पिता, नाबालिग भाई या अविवाहित बहन, विधवा बहन, विधवा बहू और पूर्व मृत बेटे के नाबालिग बच्चे को "आश्रित" शब्द के अर्थ में शामिल किया जाएगा, यदि वे पूरी तरह से या आंशिक रूप से मृत यात्री पर निर्भर हैं। 1989 के अधिनियम की धारा 123 के खंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के बीच का अंतर स्पष्ट है। जहाँ मृतक यात्री अविवाहित है या नाबालिग है, वहाँ उसके माता-पिता को केवल "आश्रित" शब्द के अर्थ में रखा गया है।

20. यह स्वीकार किया जाता है कि तीजा देवी के जीवनकाल के दौरान मूल आवेदन आगे नहीं बढ़ा। न्यायाधिकरण के समक्ष उनकी कभी जांच नहीं की गई थी। दावेदार के अनुसार, मृतक की आयु लगभग 18 वर्ष थी और अविवाहित, लेकिन न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि आवेदकों द्वारा आयु के संबंध में कोई सबूत अभिलेख पर नहीं लाया गया था। गीता देवी (अपीलार्थी), जिन्होंने स्वर्गीय तीजा देवी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपदस्थ किया, स्वर्गीय तीजा देवी की बेटी के रूप में अपनी पहचान स्थापित नहीं

कर सकी। विद्वान न्यायाधिकरण ने दर्ज किया है कि उसे मृतक के दुर्घटना स्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभिलेख पर यह न्यायालय विद्वान न्यायाधिकरण के इन निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाता है।

21. इस मामले में, मूल आवेदक के साथ-साथ वर्तमान अपीलार्थी और उत्तरदाता का मामला सं. 2 यह है कि मृतक संजय अविवाहित था, हालाँकि उसकी आयु 18 वर्ष बताई गई थी। जहां तक मृतक की उम्र का संबंध है, फिर से न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि उसकी उम्र स्थापित नहीं की जा सकी है और इस निष्कर्ष पर किसी भी आधार पर हमला नहीं किया गया है।

22. धारा 124-ए को इसके स्पष्टीकरण के साथ पढ़ने से पता चलता है कि धारा 124-ए के उद्देश्य के लिए "यात्री" शब्द में शामिल होंगे:

- “(i) इयूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी; और
- (ii) एक व्यक्ति जिसने किसी भी तिथि या वैध प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से यात्रा करने के लिए एक वैध टिकट खरीदा है और एक अप्रिय घटना का शिकार बन जाता है।”

23. तथ्यों पर, इस मामले में, यह भी विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष साबित नहीं किया जा सका कि मृतक के पास यात्रा के लिए एक वैध टिकट था। आ.सा.1 ने दुर्घटना स्थल का भी उल्लेख नहीं किया था, इसलिए इस आधार पर भी न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को बदला नहीं जा सकता है।

24. 1989 के अधिनियम की धारा 123 और 125 के संयुक्त अध्ययन से पता चलेगा कि धारा 123 के खंड (बी) के उपखंड (ii) के तहत गणना किए गए व्यक्ति द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है यदि वे पूरी तरह से या आंशिक रूप से मृतक यात्री पर निर्भर होते हैं और जहां ऐसा आश्रित नाबालिग है, तो उसके अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। अविवाहित या नाबालिग मृत यात्री के मामले में, उसके माता-पिता आश्रित होंगे। इस मामले में, न तो अपीलार्थी और न ही उत्तरदाता सं. 2 मृतक पर आश्रित होने का

दावा करते हैं, इसलिए, वे 1989 के अधिनियम की धारा 125 के संदर्भ में मुआवजे के लिए एक आवेदन नहीं रख सकते थे, इस प्रकार, एक सवाल उठता है कि क्या कुछ ऐसा है जो अपीलार्थी और उत्तरदाता सं. 2 विधायी आशय के अनुसार नहीं किया जा सकता था, 1989 के नियमों के नियम 26 के बल पर उनके प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकार करने के आधार पर उनके पक्ष में अनुमान लगाने की अनुमति दी जा सकती है।

25. इस न्यायालय के लिए, यह प्रतीत होता है कि नियम अधिनियम के कामकाज और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं और वे प्रक्रियात्मक कानून हैं। विधायी आशय का अनुमान 1989 के अधिनियम से लगाया जाना चाहिए न कि केवल उन नियमों से जो अधीनस्थ विधान का एक हिस्सा हैं।

26. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णयों पर आते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि वे निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से अलग हैं। **तुरतन समद** (उपरोक्त) के मामले में रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने दावेदार फुलमनी समद, मृतक नेल्सन समद की मां और भाई तुरतन समद के पक्ष में मुद्दों का फैसला किया था, लेकिन मुआवजे का लाभ दावेदारों के पक्ष में नहीं होने दिया क्योंकि दावा आवेदन के लंबित रहने के दौरान, मृतक की मां की मृत्यु हो गई और न्यायाधिकरण ने भाई को मृतक पर निर्भर नहीं माना, हालांकि मृतक अविवाहित बड़ा भाई था। तर्क यह था कि घटना की तारीख 26.05.1999 पर निर्भरता और 18.11.1999 पर दावा आवेदन कब दायर किया गया था, इस पर विचार करते हुए मुआवजा दिया गया होगा। उक्त संदर्भ में, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय के गद्य '13' में निम्नानुसार दर्ज किया:-

“13. उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय की यह राय है कि इस तरह के लाभकारी विधान में 90 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेना विद्वान न्यायाधिकरण का दायित्व था, लेकिन मुद्दों पर निर्णय लेने में रेलवे दावा न्यायाधिकरण के कारण देरी हुई है, उस समय तक वृद्ध और असहाय मां की मृत्यु हो गई थी, अधिनियम की धारा 123(बी)(ii) के तहत ली गई तकनीकी याचिका को देखते हुए आवेदक को लाभ के फल से वंचित करना उचित नहीं है।”

27. ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 1989 के अधिनियम की धारा 123(बी)(ii) की व्याख्या पर कानून का बयान घोषित नहीं किया है। न्यायालय ने वैधानिक योजना पर विचार नहीं किया है और इसलिए, यह न्यायालय इसी तरह का दृष्टिकोण लेने के लिए प्रेरित नहीं है।

28. अजय कुमार पंडित (उपरोक्त) के मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले में मामले का तथ्य यह था कि मृतक यात्री के पिता ने मूल दावा दायर किया था, लेकिन दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की माँ को प्रतिस्थापित किया गया था जिसने दावा आवेदन दायर किया था, लेकिन इसे विद्वान न्यायाधिकरण न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मृतक एक वास्तविक यात्री नहीं था और यह घटना रेलवे अधिनियम की धारा 123(सी)(ii) के तहत परिभाषित एक अप्रिय घटना नहीं थी। मृतक की माँ ने उच्च न्यायालय में एक अपील की, लेकिन उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, उनकी मृत्यु 25.08.2016 पर हुई। इन परिस्थितियों में, अजय कुमार पंडित और अन्य जो स्वर्गीय प्रभावती देवी (मृतक की माँ) के कानूनी उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपने नामों के प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन दायर किया। रेलवे ने प्रतिस्थापन याचिका पर आपत्ति नहीं जताई और किसी भी आपत्ति के अभाव में प्रतिस्थापन की अनुमति दी गई। जिस आदेश द्वारा प्रतिस्थापन की अनुमति दी गई थी, वह अंतिम हो गया था क्योंकि उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। इन परिस्थितियों में, एक वर्ष से अधिक समय के बाद अपील की अंतिम सुनवाई के दौरान जब रेलवे ने प्रभावती देवी के कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के संबंध में आपत्ति उठाने की मांग की, तो माननीय न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में अदालत को केवल इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दो अंकों पर दर्ज किए गए निष्कर्ष दावेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कानूनी रूप से मान्य हैं। इस न्यायालय ने पाया कि अजय कुमार पंडित

(उपरोक्त) के मामले में निर्णय पूरी तरह से अलग तथ्यों और परिस्थितियों में दिया गया है। इस मामले में, प्रतिस्थापन याचिका को हालांकि स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन साथ ही विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को गवाही देने के लिए आर-2 का आह्वान किया और अंत में न्यायाधिकरण ने पाया कि अपीलार्थी और आर-2 अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहे थे। प्रतिस्थापन की मांग करने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष दायर आवेदन में, या आ.सा.1 के बयान में कोई चर्चा नहीं है कि वे मृतक पर निर्भर थे।

29. माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा तय किये गए **कृष्णकुमार.जी.**

(उपरोक्त) के मामले में, मृतक के पिता ने 1989 के अधिनियम की धारा 124 के तहत मूल आवेदन दायर किया था दिनांक 24.02.2010 के आदेश द्वारा दावे को अनुमति दी गई। उस आदेश से पहले, मृतक की माँ जो एकमात्र अन्य आश्रित थी, 06.04.2009 पर उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में, दावेदार जो मृतक का पिता था, उसकी भी 09.04.2010 पर मृत्यु हो गई। इस समय तक, मृतक दावेदार को दिनांक 24.02.2010 आदेश के तहत देय राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता जो अपने मृत पिता का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी था, चाहता था कि निर्णय उसके पक्ष में निष्पादित किया जाए। इसलिए, उन्होंने आदेश के निष्पादन और राशियों को जारी करने का दावा करते हुए विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया, लेकिन न्यायाधिकरण ने यह विचार रखते हुए इसे खारिज कर दिया कि केवल एक आश्रित ही 1989 के अधिनियम की धारा 124-ए के तहत राशि के भुगतान का निर्देश देने वाले आदेश के निष्पादन की मांग कर सकता है।

30. **कृष्णकुमार.जी.**(उपरोक्त) के मामले में तथ्य बिल्कुल अलग थे। उक्त मामले में, दावे की अनुमति दी गई थी और धन प्राप्त करने का अधिकार पहले से ही आवेदक के पिता को दिया गया था, जिन्होंने आदेश को निष्पादित करने की मांग की थी। इस प्रकार, **कृष्णकुमार.जी.** (उपरोक्त) मामला भी वर्तमान मामले से अलग था।

31. **अर्थमुदी रामू** (उपरोक्त) के मामले में केरल उच्च न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना में उसे लगी चोटों के लिए हर्जाने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी। उक्त मामले में, मृतक ने अपनी मृत्यु से पहले न्यायाधिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था। दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद उनकी पत्नी और नाबालिग बेटी कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में अभिलेख में आए। न्यायाधिकरण ने '*व्यक्तिगत कार्य व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है*' के सिद्धांत को लागू करते हुए आवेदन करके दावा याचिका को खारिज कर दिया और एआईआर 1988 एससी 506 में प्रतिवेदित **एम. वीरप्पा बनाम एवलिन सेक्वेरिया** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि मृतक दावेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

32. **एम. वीरप्पा** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा अपकृत्यों पर आधारित था या अनुबंध पर। माननीय न्यायालय ने देखा कि दावे की प्रकृति में विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी जांच और साक्ष्य को दर्ज किये बिना यह विचार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था कि मुकदमा दावा अपकृत्य दायित्व पर आधारित है और मुकदमा समाप्त हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "*हम मुकदमा अदालत के लिए यह तय करने के लिए मामला खुला छोड़ दें कि क्या मुकदमा पूरी तरह से अपकृत्यों पर आधारित है या अनुबंध पर या आंशिक रूप से अपकृत्यों पर और आंशिक रूप से अनुबंध पर और कानून के अनुसार मामले से निपटें। यदि पूरा मुकदमा दावा अपकृत्यों पर आधारित है तो मुकदमा निस्संदेह समाप्त हो जाएगा। यदि कार्रवाई आंशिक रूप से अपकृत्यों पर और आंशिक रूप से अनुबंध पर आधारित है तो दावे का ऐसा हिस्सा जो अपकृत्यों से संबंधित है, समाप्त हो*

जाएगा और दूसरा हिस्सा बच जाएगा। यदि वाद दावा पूरी तरह से अनुबंध पर आधारित है तो वाद को पूरी तरह से परीक्षण के लिए आगे बढ़ना होगा और उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए।”

33. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के मामले पर विचार किया, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 306 के प्रावधानों का अध्ययन किया और अंततः अपील को स्वीकार कर लिया और मृतक दावेदार के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में अपीलार्थियों के दावे पर कोई आपत्ति लिए बिना गुण-दोष पर विचार करने के लिए मामले को न्यायाधिकरण को भेज दिया। इस प्रकार, माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष मामला पूरी तरह से अलग तथ्य स्थिति पर है। उक्त मामले में, पत्नी और मृतक की नाबालिग बेटी अभिलेख में आई थी, लेकिन उन्हें 'व्यक्तिगत कार्य व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है' के सिद्धांत को लागू करते हुए पराजित कर दिया गया। वर्तमान मामले में जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे आंध्र प्रदेश के फैसले में चर्चा का विषय नहीं थे।

34. इस स्तर पर, यह न्यायालय ए.आई.आर. 2000 पंजाब और हरियाणा 105 में प्रतिवेदित **भारत संघ बनाम कुमारी दीप्ति (नाबालिग)** के मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर भी चर्चा करेगा। उक्त मामले में, दुर्घटना 26.11.1998 पर पंजाब में खन्ना के पास गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस के बीच हुई थी जिसमें दावेदार-उत्तरदाता के माता-पिता कैलाश और कृष्णा और दावेदार उत्तरदाता के नाबालिग भाइयों नितिन और लोकेश की मृत्यु हो गई थी। उत्तरदाता कुमारी दीप्ति ने विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष चार दावा याचिकाएं दायर की थीं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था। भारत संघ ने केवल 8 वर्ष की आयु के नितिन और 5 वर्ष की आयु के लोकेश की मृत्यु के संबंध में दो पुरस्कारों के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी, जो उत्तरदाता-दावेदार के भाई थे। इस मामले में, एक तर्क दिया गया था कि विद्वान न्यायाधिकरण ने नितिन और लोकेश की मृत्यु के लिए गलत निर्णय दिया था क्योंकि

उत्तरदाता को नाबालिग भाइयों पर निर्भर नहीं माना जा सकता था। माननीय न्यायालय ने 1989 के अधिनियम की धारा 123 से 125 की योजना के माध्यम से, एक प्रश्न तैयार किया गया कि क्या इस मामले में उत्तरदाता को मृतक का आश्रित माना जा सकता है और अंत में उसी धारणा का उत्तर दिया कि अधिनियम की धारा 123(बी) के प्रावधान के तहत, उत्तरदाता-दावेदार का मामला उक्त धारा के खंड (i) के तहत नहीं आ सकता है।

35. निर्णय के गद्य '10' में, माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“10. जहाँ तक इन दोनों अपीलों का संबंध है, उत्तरदाता ने यह नहीं दिखाया है कि वह मृतक पर निर्भर थी। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क नहीं दिया जाता है कि उत्तरदाता वास्तव में मृतक पर निर्भर थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर भी न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए, धारा में उल्लिखित अन्य श्रेणियों के मामले में उत्तरदाता को मृतक पर निर्भर रखना संभव नहीं होगा। अधिनियम की धारा 123(बी), जो उपरोक्त पुनः प्रस्तुत की गई है, और ये अपीलें 9 वर्ष की आयु के नितिन और 5 वर्ष की आयु के लोकेश की मृत्यु से संबंधित हैं, जो उत्तरदाता के भाई थे और जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि उत्तरदाता वास्तव में मृतक पर निर्भर था, तब तक आश्रित का अनुमान लगाना उचित या कानूनी नहीं होगा। जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, "आश्रित" शब्द को अधिनियम के धारा 123(बी) में परिभाषित किया गया है और यदि वास्तविक निर्भरता नहीं दिखाई जाती है, तो उत्तरदाता को "आश्रित" की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है।”

36. अपीलार्थी और उत्तरदाता सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के इस निर्णय को पढ़ा है, लेकिन इस न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सका कि इस मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी धारा 123(बी) की कानूनी व्याख्या क्यों लागू नहीं की जा सकती है।

37. उपरोक्त की गई चर्चाओं के आलोक में जब यह न्यायालय विद्वान न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय को देखता है, तो इस न्यायालय ने पाया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने दावे के समर्थन में दायर दस्तावेजों पर विचार किया है, जैसे कि (i) रेलवे पुलिस की प्राथमिकी सह अंतिम प्रतिवेदन, सासाराम (ii) जांच प्रतिवेदन और (iii) सदर अस्पताल, सासाराम की शव परिक्षण प्रतिवेदन। न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि इन हस्तलिखित प्रतियों/छायाप्रति में से कोई भी किसी भी कानूनी व्यवसायी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित नहीं है और अंतिम प्रतिवेदन में केवल थाने का रबर मोहर है, इसलिए मामले की प्रकृति को देखते हुए विद्वान न्यायाधिकरण ने इन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया। यह न्यायालय अपीलार्थी और उत्तरदाता सं. 2 की पहचान और मृतक की आयु के संबंध में उपरोक्त दिए गए अन्य निष्कर्षों पर पहले ही ध्यान दे चुका है। ।

38. इस न्यायालय की राय में, न्यायाधिकरण के पास इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को आमंत्रित करने के लिए कोई त्रुटि नहीं की। इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायाधीश)

राजीव/तुषारिका-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।